दिनांक–29.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सुपौल जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सुपौल जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से 07 का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर शेष सभी योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोक लेखा समिति की वर्ष 2018–19 की 01 एवं 2020–21 की 02 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग, 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वॉ वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DDC द्वारा बताया गया कि 12वॉ वित्त आयोग में 07 करोड रूपये की UC एक सप्ताह के भीतर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृ0पृ0उ0

(ख) Post CFMS Period में कुल 383.98 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से 14वॉ वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

III. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3570 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1725 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 1369 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद)

IV. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 550 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 532 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा 16 मामले लंबित है। इस संबंध में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

V. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 05 मामलों के विरूद्ध 04 मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. निगरानी से संबंधित मामले–

सुपौल जिले में कुल 03 मामले निगरानी के लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी मामलो का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 71, 62 एवं 45 Aspiration के विरूद्ध सभी का निष्पादन हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल निर्मित 95 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध सभी का हस्तांतरण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 94 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 94 में RTPS केन्द्र, 62 में विद्युत कनेक्शन, 27 में डाकघर, 11 में NOFN एवं 07 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। केवल 48 PSB में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 95 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 61 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 23 PSB के विरूद्ध 19 PSB का ही निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। छातापुर प्रखंड के मोहम्मरगंज पंचायत में द्वितीय तल लिंटर स्तर एवं निर्मली प्रखंड के हरियाही पंचायत में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। कुल 02 पंचायतों में PSB का निर्माण कार्य फिनिशिंग स्टेज में है। निदेश दिया गया कि जो पंचाचत सरकार भवन फिनिशिंग स्टेज में है, उसे 15

लगातार.....

दिनो के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतो में PSB निर्माणाधीन है, वहाँ कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 05 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से किसी का भी निराकरण नहीं हुआ है। सरोजाबेला एवं चिलौनी दक्षिण पंचायतो में भूमि अप्राप्त है। वीणा पंचायत में प्राप्त भूमि शिक्षा विभाग की है। सिसौनी एवं बलवा पंचाचतों में चिन्हित भूमि बांध के अंदर स्थित है। निदेश दिया गया कि वीणा पंचायत में PSB के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। यदि किसी पंचायत में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 18 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध मात्र 06 पंचायतों में भूमि उपलब्ध है, जिसमें से TA द्वारा 05 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। 05 पंचायतो में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर सभी में पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है। जिन पंचायतों में भूमि अप्राप्त है तो भूमि अनुपलब्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 174 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 102 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से 81 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 32 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से 31 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 20 पंचायतो में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में अबतक TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के TA के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

X. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 49 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। DPRO ने बताया कि सर्वेक्षित शमशान/मुक्तिधाम का आकड़ा त्रुटिपूर्ण है। DPRO एवं सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से

लगातार.....

संचालित शमशान/मुक्तिधाम का पुनः त्रुटिरहित सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

वसंतपुर, किशनपुर, निर्मली, पिपरा, राघोपुर एवं सुपौल प्रखंडो में दिनांक– 01.04.2026 से अबतक शून्य अंत्येष्टि प्रतिवेदित की गयी है। प्रतीत होता है कि संबंधित BPRO द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। DPRO को निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO से इस संबंध में स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 02, पंचायत समिति में 26 एवं ग्राम पंचायत में 39 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

(क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	36.19%
02	पंचायत समिति	47.16%
03	ग्राम पंचायत	56.96%

पिपरा प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) बसंतपुर प्रखंड के बनैली पट्टी पंचायत, मरौना प्रखंड के हरारी पंचायत एवं सुपौल प्रखंड के गोथ बरूआरी पंचायत में व्यय की गयी राशि काफी कम है। उक्त प्रखंडो के BPRO ने बताया गया कि संबंधित मुखिया द्वारा अनावश्यक रूप से भुगतान करने में विलंब किया जाता है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 860 के विरूद्ध 249, पंचायत समिति में 1215 के विरूद्ध 180 एवं ग्राम पंचायत में 12557 के विरूद्ध 1648 योजना ही पूर्ण की गयी है।

लगातार.....

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. पिपरा प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. बसंतपुर प्रखंड के बनैली पट्टी पंचायत, मरौना प्रखंड के हरारी पंचायत एवं सुपौल प्रखंड के गोथ बरूआरी पंचायत के मुखिया पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	22.88%
पंचायत समिति	45.24%
ग्राम पंचायत	40.20%

मरौना एवं त्रिवेणीगंज प्रखंडो के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) मरौना प्रखंड में 04, त्रिवेणीगंज प्रखंड में 03, किशनपुर, पिपरा एवं राघोपुर प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 298 के विरूद्ध 104, पंचायत समिति में 479 के विरूद्ध 192 एवं ग्राम पंचायत में 2688 के विरूद्ध मात्र 1704 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. मरौना एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO शून्य व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

लगातार.....

4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक सुपौल जिले में 6670 लक्ष्य के विरूद्ध 6470 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की संख्या क्रमशः 01 एवं 00 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी सुपौल प्रखंड में शून्य तथा किशनपुर प्रखंड में मात्र 5% का भुगतान किया गया है।

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 06 मामलो के विरूद्ध 03 का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 28.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में कुल 91% सोलर लाईट ON पाई गयी है, जिसमें से मरौना प्रखंड में ON पाई गई लाइटो का प्रतिशत कम है।

यह भी पाया गया कि कुल 11 प्रखंडो में से मात्र 08 प्रखंडो के BPRO के द्वारा ही सोलर लाईट का निरीक्षण किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। साथ ही किशनपुर, निर्मली एवं राघोपुर प्रखंडो के BPRO द्वारा क्रमशः 09, 10 एवं 17 लाईटो का ही निरीक्षण किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं JICR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. पंचायत सचिव के द्वारा मरौना प्रखंड के Inspection में OFF पाई गयी लाईटों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

बसंतपुर, प्रतापगंज, सरायगढ़ भाप्तियाही, किशनपुर, निर्मली एवं राघोपुर प्रखंडों के BPRO से इस संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रशाखा–03)

लगातार.....

XIV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XV. लंबित न्यायिक वाद :–

सुपौल जिले में 04 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा–9)

XVI. e- GRAM KACHAHARI :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी)

XVII. विधान सभा/परिषद–

सुपौल जिले में कुल 03 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा)

XVIII. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। सुपौल जिले में भी 48 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार.....

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14585/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, सुपौल/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/2026
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14585/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/10/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14585/पं०रा० पटना, दिनांक 13/10/2026
प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/10/26
(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी